साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कालिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 7 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 4 अक्टूबर 2023 से 9 अक्टूबर 2023 पेज : ७ कीमत : 3 रुपये

पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने जीते दो अवार्ड

भोपाल विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने फिर शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। प्रदेश के ग्राम मडला और खोखरा 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुने गए हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम् कन्वेंशन सेंटर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पन्ना के मडला ग्राम को स्वर्ण श्रेणी और सीधी के खोखरा ग्राम को कांस्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में सचिव, पर्यटन, भारत सरकार सुश्री वी. विद्यावती द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से अपर प्रबंध संचालक श्री विवेक श्रोत्रिय और संचालक कौशल डॉ. मनोज कुमार सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया।

प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने हर्ष जताते हुए ग्रामीण परियोजना विकास में प्रयासरत सभी अधिकारियों और सहभागी संस्थाओं को बधाई दी है। उन्होंने आशा की कि सभी के एकजुट प्रयासों से मध्यप्रदेश को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अग्रणी बनायेंगे।

उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होम-स्टे के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 795 ग्रामों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थे7 इसमें से 35 ग्रामों को स्वर्ण श्रेणी में नामांकित किया गया। इन 35 ग्रामों में से शीर्ष 5 ग्रामों को स्वर्ण श्रेणी में सम्मानित किया गया, जिसमे मध्यप्रदेश का मडला ग्राम शामिल है। सम्मान समारोह के दौरान सहयोगी संस्था से श्री कीर्ति वर्धन सिंह, श्री सार्थक त्यागी, ग्राम मडला से श्री लखन अहिरवार एवं ग्राम खोखरा से श्री जगदीश सिंह और श्रीमती कौशल्या सिंह उपस्थित रहे।

पन्ना का मडला गाँव, खूबसूरत केन नदी के किनारे स्थित है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व का एक गेट भी है। सीधी का खोखरा गाँव, संजय दूबरी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित है7 दोनो गाँव ग्रामीण पर्यटन भ्रमण, होम-स्टे अनुभव, स्थानीय भोजन, कला और शिल्प में अनूठे हैं। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य इन ग्रामों की विशेषता है। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड न केवल पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्यरत है, अपितु संतुलित और संवहनीय पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। यह सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम कर मध्यप्रदेश को सम्पूर्ण पर्यटन अनुभव कराने वाले गंतव्य के रूप में स्थापित करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख टूरिज्म बोर्ड द्वारा रिस्पोंसिबल टूरिज्म मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है मध्यप्रदेश को विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के कारण बघेलखंड, बुंदेलखंड, चंबल, मालवा, निमाड़ और महाकौशल जैसे छः प्रमुख सांस्कृतिक अनुभव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रचलित पर्यटन स्थलों के समीपस्थ 100 ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से रोमांचित हो उठे देशभर से आए सुपरबाइक राइडर्स

भोपाल राष्ट्रीय उद्यानों के बीच से गुजरने के रोमांच, पचमढ़ी एवं तामिया के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए देशभर से आये 25 सुपरबाइक राइडर्स के सफर का समापन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स पर हुआ। गत 20 सितंबर को भोपाल से निकले राइडर्स पचमढ़ी, सतधारा, तामिया पातालकोट, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, भेड़ाघाट होते हुए भीमबेटका पहुंचे। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिवशेखर शुक्ला ने राइडर्स को शुभकामनाएं दी है। लगभग 1400 कि.मी. का फासला तय करने वाले राइडर्स को भीमबेटका पर टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त संचालक डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। 'राइडर्स इन द वाइल्ड' को मस्टेच एस्केप्स द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया था। मध्यप्रदेश को एक प्रमुख 'एडवेंचर डेस्टिनेशन' के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से टूरिज्म बोर्ड द्वारा लगातार दूसरे साल 'राइडर्स इन द वाइल्ड' का आयोजन किया गया।

अमेरिका के नियाग्रा फाल जैसा बृहस्पति कुंड में पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे-मंत्री श्री सिंह

खनिज मंत्री ने विकास व सौंदर्यीकरण के कार्यों का किया भूमि-पूजन

भोपाल बृहस्पति कुंड को सुंदर और भव्य स्वरूप दिया जाएगा। पर्यटन विकास के साथ यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। भविष्य में यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने यह बात बुधवार को बृहस्पति कुंड में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के भूमि-पूजन अवसर पर कहीं। मंत्री श्री सिंह ने 3 करोड़ 2 लाख 70 हजार रुपए लागत राशि के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया। पर्यटन विभाग द्वारा बृहस्पति कुंड में पर्यटकों की सुविधा के लिए रेलिंग, शेल्टर, शौचालय, कैफेटेरिया, पार्किंग इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। तकनीकी टीम द्वारा परीक्षण के बाद यहां ग्लास ब्रिज का निर्माण भी करवाया जाएगा।

श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बृहस्पति कुंड राम वन पथ गमन में शामिल महत्पवूर्ण स्थान भी है। सारंगधाम सहित भगवान राम की स्मृतियों से जुड़े स्थलों के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। इन सभी स्थानों के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण का कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में बृहस्पति कुंड का स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के नियाग्रा फॉल जैसा प्रतीत होता है। यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह स्थान बारिश के मौसम में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहता है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन विभाग के माध्यम से विकास कार्यों की यह बड़ी उपलब्धि है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पन्ना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए गए हैं। पन्ना-पहाड़ीखेरा मार्ग का कार्य निर्माणाधीन है। पहाड़ीखेरा-मझगुवां मार्ग का भूमिपूजन भी शीघ्र किया जाएगा। यह रोड 82 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांग पर छतैनी-बृजपुर, मठली-पाठा, दमचुआ-बृजपुर, हरदुआ-बिल्हा, सारंग-किटहा मार्ग की सौगात प्रदान की गई है। हरदुआ के पास चाचई बांध के लिए भी राशि स्वीकृत हो गई है। आगामी दिनों में बृहस्पति कुंड से सीधे इमलोनिया और पनारी को जोड़ा जाएगा। मंत्री ने खनिज विभाग से 110 करोड़ की राशि से सड़क निर्माण सहित कई अन्य विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि के संबंध में भी अवगत कराया। श्री सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। क्षेत्र की पानी समस्या दूर करने के लिए मझगांय बांध से पानी लिफ्ट करके पानी लाया जाएगा। खनिज मंत्री ने इसके पहले ग्राम कल्याणपुर में गांधी ग्राम-कल्याणपुर मार्ग का भूमिपूजन भी किया। कुल 2.90 किलोमीटर की यह सड़क 2.5 करोड़ रूपए की लागत से बनेगी। श्री बृजेन्द्र गर्ग ने कहा कि पर्यटक स्थल बृहस्पति कुंड की विकास और सौंदर्यीकरण कार्य से अलग पहचान बनेगी। इसके अलावा पन्ना से चित्रकूट तक बेहतर सड़क बनने से आवागमन भी आसान हो सकेगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रभा गौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कार्यपालन यंत्री के.के. चौरसिया, जिला पर्यटन प्रबंधक अदिति चंसौरिया, जिला पुरातत्व पर्यटन परिषद के सदस्य मुकेश कुमार पाण्डेय, सरपंच राजकुमारी सिंह, विष्णु पांडेय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उपयंत्री रवि त्रिपाठी द्वारा किया गया।

वनोपज के माध्यम से गरीब कल्याण की अनेक संभावनाएँ

भोपाल वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने प्रशासन अकादमी में ''राष्ट्रीय महुआ कानक्लेव'' आयोजन के अवसर पर कहा कि वनोपज के माध्यम से गरीब कल्याण की दिशा में व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश में महुआ संग्राहकों को बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। महुआ संग्रहण के लिए इन परिवारों को नि:शुल्क जाल उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे उत्तम गुणवत्ता का महुआ संग्रहित किया जा सके।

वन मंत्री डॉ. शाह ने महुआ के सामाजिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक उन्नयन पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि मध्यप्रदेश का महुआ संग्रहण में अग्रणी स्थान है। अभी तक महुआ वनोपज का सीमित उपयोग होता था, इसी प्रकार वनवासियों को महुआ वनोपज का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता था। राज्य शासन द्वारा की गई पहल से संग्राहकों को अब महुआ संग्रहण का अच्छा मूल्य प्राप्त हो पा रहा है। इसके लिए वनवासियों को महुआ पेड़ के नीचे जाल बिछाकर महुआ संग्रहण के लिए जागरूक किया गया है। वन मेले के माध्यम से महुआ विपणन में अब बेहतर कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विभागीय रोपणों में 50 प्रतिशत वनोपज प्रजाति के पौधों के रोपण का निर्णय लिया गया है। इससे भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में इमारती लकड़ी के साथ-साथ लघु वनोपज भी प्राप्त हो सकेगी। हाईटेक टिशुकल्चर नर्सरी में महुए के पौधों को तैयार किये जायेंगे। वनमंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने इस अवसर पर मध्यप्रदेश में लघुवनोपज की उत्पादन क्षमता का आंकलन प्रतिवेदन का विमोचन किया। वनमेला-2022 की चित्रमयी प्रस्तुति का दस्तावेज जारी किया। एम.एफ.पी.पार्क के हर्बेरियम डाटाबेस को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य न्यूयार्क बॉटनिकल गार्डन की वेबसाइट ''इडेक्स हर्बेरियम डाटाबेस सिस्टम'' वेबसाईट का लोकार्पण किया। उन्होंने वन-धन नैचुरल्स की नवीन पैकेजिंग का लोकार्पण किया। वनमंत्री द्वारा प्रदेश में फुडग्रेड महुआ संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आठ जिला वनोपज सहकारी यूनियनों का सम्मान किया। अपर मुख्य सचिव वन श्री जे.एन. कांसोटिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका से महुआ जुड़ा हुआ है। इसके विकास तथा विपणन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधान मुख्य संरक्षक एवं वनबल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता ने कहा कि महुए की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में विगत कुछ वर्षों में किये गये प्रयासों के परिणाम मिलना शुरू हो गये हैं। प्रबंध संचलाक मध्यप्रदेश राज्य वनोपज संघ श्री पुष्कर सिंह ने कहा कि महुए पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों से भविष्य में महुआ संग्रहणकर्ताओं को लाभ प्राप्त होगा। वरिष्ठ वन अधिकारी, विषय विशेषज्ञ एवं महुआ संग्राहक उपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.पार्क डॉ. दिलीप कुमार ने समापन अवसर पर महुआ कानक्लेव डिक्लेरेशन के माध्यम से इस एक दिवसीय आयोजन के तीन सत्रों के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा की गई चर्चा के आधार पर महुआ।

शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोडमेप तैयार करें -राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु

भोपाल (एजेंसी)राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि शहरों और नागरिकों की जरुरत का आंकलन कर विकास का रोडमेप तैयार किया जाना चाहिये। जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर करते हुये उन्होने स्मार्ट शहरों में किये जा रहे कार्यों को सकारात्मक पहल बताया। इस दिशा में और टिकाऊ विकास पर और अधिक काम किये जाने की जरूरत है। शहरी विकास में समग्र निवेश पिछले दशकों में दोगुना से अधिक हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन का इसमें बड़ा योगदान है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कान्क्लेव-2023 में सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होने मध्यप्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने आईसी अवार्ड सेरेमनी में विजेता शहरों और राज्यों को पुरस्कार वितरित किए। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि इन्दौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखा है। इंदौर देश की स्मार्ट सिटीज में भी सबसे ऊपर है। उन्होंने इंदौर के निवासियों, जन-प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना की। राष्ट्रपति ने इंडिया स्मार्ट सिटीस अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्यप्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर राज्य के सभी निवासियों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य के सभी स्मार्ट शहरों में किए जा रहे कार्यों से जुड़े लोगों की सराहना भी की। साथ ही सर्वश्रेष्ठ केन्द्र शासित प्रदेश का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ और राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु तथा संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी बधाई दी।

राष्ट्रपति ने अलग-अलग श्रेणियों में 66 पुरस्कार विजेता स्मार्ट शहरों और राज्यों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 46 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाएगी, तब हमारे 50 प्रतिशत से अधिक देशवासी शहरी क्षेत्रों में रहेंगे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग दो-तिहाई योगदान करते हैं। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से यह संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोडमेप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है - वह है क्लाईमेट चेंज इस संदर्भ में क्लाईमेट स्मार्ट सिटीस असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया था, वह इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि शहरों में एनर्जी एफीसियेंसि के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है लेकिन इन क्षेत्रो में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। एसडीजी 11 का लक्ष्य है - मेक सिटीज एण्ड ह्यूमन सेटेलमेंट इन्क्लूसिव, सेफ, रिसाईलेंट एण्ड सस्टेनेबल - यह लक्ष्य शहरों के सम्पूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता जाहिर की कि शहरी विकास में देश का समग्र निवेश पिछले दशक के दौरान, पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक हो गया है। बेस्ट प्रेक्टिसेस को लागू करने और टिकाऊ बिजनेस मॉडल्स विकसित करने में स्मार्ट सिटीस मिशन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अर्बन-20, जी-20 का एक सब ग्रुप था। अर्बन-20 ने शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से एक सामूहिक संदेश भी दिया गया कि सतत विकास की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने में शहरों के प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व के बेस्ट मेनेज्ड शहरों की बेस्ट प्रेक्टिसेस, उनके बिजनेस मॉडल्स से हमें सीखना चाहिए और अपने सफल प्रयासों को भी अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए। लोकल और ग्लोबल स्तर पर सहयोग करना समग्र तथा सतत विकास के लिए आवश्यक है। सभी 100 स्मार्ट शहरों में इन्टीग्रेटेड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर संचालित हैं, जो डेटा का उपयोग करके उस पर आधारित निर्णय ले रहे हैं। नागरिकों खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी सर्विलैंस कैमरे आज कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद कर रहे हैं। इन 100 स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे प्रयास हमारे 4800 से अधिक कस्बों और शहरों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। पूरे देश में सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ नेबरहुड को विकसित करना है। कई स्मार्ट शहरों में ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि लोग खुद जिम्मेदार बनें और अपने शहर तथा निवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि इंदौर, सूरत, कोहिमा, श्रीनगर और कई अन्य शहरों ने जन-भागीदारी द्वारा सुव्यवस्थित शहरीकरण के सफल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसी स्मार्ट शहरों में लैण्ड रिक्लेमेशन किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने सुझाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से शहरों पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र की जनता का जीवन भी बेहतर होगा।

दर्द की दवा को विकसित करने के लिए एआइ की सहायता से चूहों के व्यवहार का परीक्षण

बेंगलूरु भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) के वैज्ञानिक लोगों के पुराने दर्द (क्रोनिक पेन) के उपचार की दवा खोजने के लिए एआइ की मदद ले रहे हैं। आइआइएससी के वैज्ञानिक चूहों पर परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण के दौरान चूहों के व्यवहार के विश्लेषण के लिए एआइ की मदद ली जा रही है। शोधकर्ताओं ने एआइ की मदद से चूहों के व्यवहार का एक मॉडल तैयार किया है। इससे पता चल सकेगा कि दवाओं से चूहों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शोधार्थियों ने बताया कि चूहों के व्यवहार से जानकारी मिल सकेगी कि दवाओं से उनका दर्द कम हुआ है या नहीं। चूहों पर प्रयोग सफल होने के बाद दवाओं का लोगों पर प्रयोग किया जा सकेगा। यह अध्ययन हाल ही न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया।

जंगलों पर छाया जलवायु परिवर्तन का साया, पेड़ों से गायब हो रहे फल, पक्षियों ने छोड़ा उपवन

तेलोली गांव जोकि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में प्राचीन अंशी जंगल के किनारे स्थित है वहां रहने वाले ग्रामीण जंगल में आते ऐसे बदलावों को अनुभव कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखे गए। इसके लिए बढ़ता तापमान, बारिश के पैटर्न में आता बदलाव और मौसम की चरम घटनाएं जिम्मेवार हैं। डर है कि यह अनजाने बदलाव आगे चलकर व्यापक घटनाओं की वजह बन सकते हैं। इस बात की पुष्टि भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने 2020 में किए अपने तकनीकी अध्ययन में भी की है कि अंशी वन 1951 से 2019 के बीच जलवायु में आते बदलावों और उनके प्रभावों के लिए एक हॉटस्पॉट है।

एक स्थानीय ग्रामीण 55 वर्षीय सुरेश बाबू गावड़ा ने जंगल और गांव के बीच लगे एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए डाउन टू अर्थ (डीटीई) को बताया कि, इस साल, हमारे गांव या आस-पास के इलाकों में पेड़ों पर कोई वेटे हुली फल नहीं लगे। गौरतलब है कि वेटे हुली, जिसे मंकी जैक के नाम से भी जाना जाता है। स्वाद में खट्टे इन फलों का उपयोग स्थानीय लोग खासकर स्थानीय कंद वाली सब्जियों में मसाले के रूप में करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मंकी जैक का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन इस बार यह इतना घट गया कि जिसको देखकर लोग हैरान हैं। इस बारे में पास के कुंभारवाड़ा गांव के शांताराम कामत का कहना है कि पहले हमें एक पेड़ से करीब 50 क्विंटल फल मिलता था, जो हाल के वर्षों में घटकर 30 से 40 क्विंटल रह गया है। लेकिन 2023 ने तो सभी को बड़ा झटका दिया है। कामत काली फार्मर्स प्रोड्यूसर नामक कंपनी चलाते हैं और वन पारिस्थितिकी के स्थानीय विशेषज्ञ भी हैं। बता दें कि मंकी जैक, एक अर्ध-सदाबहारी वृक्ष हैं, जो अंशी जंगल और उसके आसपास उत्तरी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के अन्य क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उगता है। यह पेड़ शरद ऋतु के दौरान थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनमें फरवरी के आसपास फूल आते हैं और अप्रैल से मई के बीच फलों के लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्थानीय इनका उपयोग भोजन, चारे, लकड़ी और औषधीय प्रयोजनों के लिए करते हैं। आम तौर पर यह पेड़ गहरी अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपते हैं और उन्हें साल में औसतन 700 से 2,000 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। लेकिन 2023 में बहुत कम बारिश हुई हुई है। एक मार्च से 31 मई के बीच उत्तर कन्नड़ जिले में सामान्य से 59 फीसदी कम बारिश हुई। इस बारे में कामत ने बताया कि, होली और गुड़ी पड़वा के दौरान हमेशा लगातार मध्यम तीव्रता की बारिश होती है, यह सिलसिला दोनों प्री-मॉनसून सीजन में जारी रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे बताया कि, या तो बारिश नहीं हो रही है या भारी से अत्यधिक बारिश हो रही है। बारिश की कमी का असर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। जब डीटीई ने कादरा से, जहां से अंशी वन प्रभाग शुरू होता है, कुंभारवाड़ा तक की यात्रा की तो वहां जंगल के कई हिस्से सूखे पड़े थे। बारिश की कमी का असर जंगलों से मिलने वाले अन्य उत्पादों जैसे शहद और कंद को भी प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, शहद के अच्छे उत्पादन के लिए मानसून से पहले अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है। कामत ने समझाया कि जब बारिश नहीं होती या कम होती है, तो शहद गाढ़ा हो जाता है, जिससे कुल उत्पादन कम हो जाता है। पेड़ों के फूलने के लिए भी बारिश की आवश्यकता होती है, जो मधुमक्खियों के लिए शहद पैदा करने का अमृत स्रोत है।

गावड़ा ने बताया कि, चार-पांच साल पहले, वे एक छत्ते से करीब 20 किलो शहद इकट्ठा करते थे। यह अब घटकर पांच से दस किलो रह गया है। इसी तरह जंगल के दूसरे कई अन्य पौधों और पेड़ों को भी अंकुरण और अन्य गतिविधियों के लिए मानसून से पहले अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है। फिर मानसून की बारिश उनके आगे विकास में सहायता करती है। कामत का कहना है कि इसके बावजूद मुख्य जंगलों के अंदर इसकी निगरानी नहीं की जा रही और हमारे पास किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई आंकड़े भी नहीं है। एक फसल जिससे इस स्थिति को समझा जा सकता है वह है कंद, जिसकी सिंचाई और देखभाल स्थानीय किसानों द्वारा की जाती है। हालांकि इसके बावजूद जंगलों के बाहर इसकी वृद्धि प्रभावित हुई है। वहीं कामत के मुताबिक, जंगल के अंदर तो स्थिति कहीं ज्यादा भयावह होगी। एक और असामान्य और पहले कभी न देखी गई घटना तेलोली गांव के ठीक बाहर वन क्षेत्र के अंदर 21 जुलाई, 2021 को हुआ भूस्खलन था। इस दौरान जंगल को जो क्षति हुई, उसका असर मई 2023 में भी दिखाई दे रहा था। गावड़ा का कहना है कि, उस दिन थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा बारिश हुई और पहाड़ी का किनारा नीचे खिसक गया। उनके मुताबिक %%बारिश से इस तरह जंगल का बह जाना इस क्षेत्र में पहली बार हुआ है। बारिश के पैटर्न में जिस तरह बदलाव आए हैं उसके कारण अन्य पारिस्थितिकीय प्रभाव भी पड़े हैं जैसे तितलियों की संख्या में कमी के साथ-साथ विविधता में भी कमी आई है। इतना ही नहीं इस इलाके में आने वाले प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति में भी कमी देखी गई है। ऐसा ही कुछ %बटकी% के साथ भी देखने को मिला है। इस पक्षी को हर साल अगस्त से जनवरी के बीच इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में देखा जा सकता था। लेकिन गावड़ा के मुताबिक इस प्रजाति के दो पक्षियों को आखिरी बार नवंबर 2022 में देखा गया था।

विकास के लिए हरियाली की बलि, इंदौर में घट गए 10 प्रतिशत जंगल

इंदौर। टू-टियर सिटी में शामिल इंदौर में विकास कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। तीन साल के भीतर कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है। इसमें मेट्रो से लेकर इंदौर-खंडवा राजमार्ग और इंदौर-सनावद ब्राडगेज सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट को आकार देने के लिए जिले में जगह-जगह वनभूमि को अधिग्रहित किया गया है। इस कारण इंदौर वनमंडल में दस प्रतिशत वनक्षेत्र घट गया है।

इंदौर वनमंडल में इंदौर-महू, चोरल और मानपुर का 11 हजार हेक्टेयर का वनक्षेत्र है। विभिन्न प्रोजेक्ट शुरू होने से एक हजार हेक्टेयर वनभूमि कम हो चुकी है। जंगल का दायरा घटने से हरियाली कम हुई है। इसके पीछे दूसरी वजह अवैध कटाई भी है। वैसे इन दिनों नई अनाज मंडी के लिए माचल वन क्षेत्र में वन भूमि देने को लेकर सर्वे का काम चल रहा है। महू-सनावद के बीच बड़ी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके लिए रेलवे और वन विभाग ने सर्वे किया। उसमें 215 हेक्टेयर वनभूमि चिन्हित की गई। इसमें इंदौर वनमंडल की 195 और बड़वाह वनमंडल की 30 हेक्टेयर भूमि में मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए करीब चालीस हजार पेड़ काटे गए हैं। बदले में विभाग को झाबुआ में जमीन मिली है। साथ ही पौधारोपण के लिए भी रेलवे से राशि मिलने का इंतजार हो रहा है। इंदौर-खंडवा और एदलाबाद राजमार्ग का काम डेढ़ साल पहले शुरू हुआ है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008